



कृषि आधारित सतत आजीविका के लिए उद्यमिता विकास

रवींद्र नाथ पडारिया¹, ऐश्वर्या एस.², स्वीटी मुखर्जी¹, सिमरन पुंडीर¹ और प्रीति प्रियदर्शिनी³

भारतीय कृषि के सामने चुनौतियां सिर्फ उत्पादन तक ही सीमित नहीं हैं। आज ग्राहक सुरक्षित, पौष्टिक, ट्रेस करने योग्य और मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों की मांग करते हैं, जबकि घरेलू और वैश्विक बाजार अब सिर्फ कच्चे उत्पाद के बजाय गुणवत्ता, ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग और कुशल लॉजिस्टिक्स को ज्यादा महत्व देते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, परिशुद्ध खेती, ई-कॉमर्स और डेटा-आधारित परामर्श सेवाओं में तेजी से हो रहे विकास कृषि मूल्य श्रृंखला को पूरी तरह से बदल रहे हैं। इन बदलावों के कारण किसानों को उत्पादन कौशल के साथ-साथ उद्यमिता से जुड़ी क्षमताएं भी विकसित करने की जरूरत है। बदलते हुए इस दौर में, कृषि अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रह सकती। टिकाऊ आजीविका को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा मूल्य वाले उद्यमों, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, कृषि-सेवाओं, डिजिटल कृषि, कस्टम हायरिंग केंद्र, एग्री-टूरिज्म, पशुपालन उद्यमों और बाजार आधारित नवाचार की ओर विविधता लाने की जरूरत है। इस बदलाव से 'एग्रीप्रेन्योरशिप' (कृषि-उद्यमिता) का उदय हुआ है, जो लाभदायक, मजबूत और रोजगार उन्मुख ग्रामीण उद्यम बनाने के लिए वैज्ञानिक कृषि को व्यावसायिक नवाचार के साथ जोड़ता है। एग्रीप्रेन्योरशिप किसानों को प्राथमिक उत्पादक की भूमिका से आगे बढ़कर कृषि मूल्य श्रृंखला में प्रोसेसर, सेवा प्रदाता, निर्यातक, इनोवेटर और बिजनेस लीडर के तौर पर सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत 2047' के विजन की ओर बढ़ रहा है, एग्रीप्रेन्योरशिप न केवल आजीविका का एक वैकल्पिक जरिया बनकर उभर रही है, बल्कि ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने, खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने और एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ कृषि अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जरूरत भी बन गई है। भारतीय कृषि अब केवल उत्पादन बढ़ाने पर निर्भर नहीं रह सकती; भविष्य इसी में है कि हर खेत को एक उद्यम और हर किसान को एक उद्यमी के रूप में विकसित किया जाए।

पिछले पांच दशकों में भारतीय कृषि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे देश अनाज, दालों, दूध, फलों, सब्जियों, मसालों और मछली उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है।

आज भी, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र भारत के 46.1 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन का 17.8 प्रतिशत योगदान करते हैं। 1.4 अरब से ज्यादा लोगों के लिए

¹भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; ²भाकृअनुप-केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार; ³बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर



पशुपालन से सतत आजीविका



ग्रेडिंग से बढ़ता उत्पाद का बाजार मूल्य

एग्रीप्रेन्योरशिप: भारतीय खेती का भविष्य

भारतीय खेती का विकास ऐतिहासिक रूप से तकनीकी क्रांतियों से आगे बढ़ा है—जैसे 'हरित क्रांति' जिसने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और 'श्वेत क्रांति' जिसने डेरी सेक्टर को बदल दिया। आज, खेती एक और बदलाव के दौर में है—ऐसा बदलाव जो सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि वैल्यू बनाने, रोजगार उत्पन्न करने और टिकाऊ ग्रामीण उद्यम बनाने पर केंद्रित है। यह बदलाव 'एग्रीप्रेन्योरशिप' (खेती-बाड़ी से जुड़ा उद्यम) में दिखता है, जो खेती को सिर्फ उत्पादन की गतिविधि मानने के बजाय उसे एक समेकित व्यावसायिक पारितंत्र के तौर पर चलाने की सोच है। एग्रीप्रेन्योरशिप खेती के दायरे को सिर्फ फसल उगाने से आगे ले जाती है। यह उत्पादन को नवाचार, मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ती है, जिससे किसान एग्रीकल्चर मूल्य श्रृंखला का ज्यादा हिस्सा हासिल कर पाते हैं। ऐसे दौर में जब ग्राहक अच्छी क्वालिटी वाले, ट्रेस करने योग्य, पौष्टिक और मूल्य वर्धित उत्पादों की मांग कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन सिर्फ उत्पादन की मात्रा से तय नहीं होता, बल्कि बाजार को समझने, ग्राहकों की पसंद के हिसाब से काम करने और लगातार नवाचार करने की क्षमता से तय होता है। इसलिए, एग्रीप्रेन्योर न केवल खेत में, बल्कि कृषि उत्पाद की पूरी यात्रा के दौरान 'खेत से लेकर ग्राहक की थाली तक' वैल्यू बनाते हैं। यह सोच में बदलाव किसानों की भूमिका को पूरी तरह से नए नजरिए से परिभाषित करता है। पारंपरिक रूप से, किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने और कच्चा माल बेचने पर ध्यान देते रहे हैं और अक्सर बिखरे हुए बाजारों में 'प्राइस टेकर' (बाजार द्वारा तय कीमत मानने वाले) के तौर पर काम करते हैं। इसके उलट, एग्रीप्रेन्योर बाजार की जरूरतों को पहचानते हैं, ग्राहकों की पसंद के हिसाब से उत्पाद बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड बनाते हैं और ग्राहकों, रिटेलर्स और प्रोसेसरों के साथ सीधे संबंध बनाते हैं। उनकी सफलता को सिर्फ प्रति हैक्टर पैदावार से नहीं, बल्कि मुनाफे, उद्यम के विकास, ग्राहक संतुष्टि और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस से मापा जाता है।



यांत्रिकीकरण से लाभकारी बनती खेती

आहार और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, यह क्षेत्र ग्रामीण आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से की आजीविका का प्रमुख आधार होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, भारतीय कृषि को कई तरह की संरचनात्मक, आर्थिक, जलवायु और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो ग्रामीण आजीविका की स्थिरता के लिए चुनौतियां हैं। पहली और शायद सबसे अहम चुनौती कृषि भूमि का निरंतर विखंडन और उसका घटता आकार है।

हालिया कृषि जनगणना के अनुसार, 86.1 प्रतिशत भारतीय किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं और दो हैक्टर से कम जमीन पर खेती करते हैं; औसत खेती योग्य जमीन घटकर लगभग 1.08 हैक्टर रह गई है। जमीन के ऐसे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से मशीनीकरण सीमित हो जाता है, बड़े पैमाने पर खेती के फायदे नहीं मिल पाते, मोल-भाव करने की क्षमता कम हो जाती है और व्यावसायिक कृषि को अपना कठिन हो जाता है।

मुनाफा एक और बड़ी चिंता का विषय बन गया है। जहां खाद, अच्छे बीज, कीटनाशक, मशीनरी, सिंचाई, ईंधन और खेती में लगने वाली मजदूरी की बढ़ती कीमतों के कारण खेती की लागत काफी बढ़ गई है, वहीं फसल की बिक्री की कीमतें अक्सर अस्थिर और अनिश्चित रहती हैं।

किसानों को अक्सर ज्यादा उत्पादन के बावजूद कम मुनाफे जैसी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार में आवक में उतार-चढ़ाव, भंडारण की

सामूहिक उद्यम और एग्रीबिजनेस सेवाएं

संस्थागत नवाचारों ने एग्रीप्रेन्योरशिप (कृषि-उद्यमिता) इकोसिस्टम को काफी मजबूत किया है। देशभर में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि छोटे किसानों को एक साथ लाया जा सके, बाजार से जुड़ाव मजबूत हो और सामूहिक प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को आसान बनाया जा सके। पारंपरिक सहकारी समितियों के बजाय व्यावसायिक उद्यमों के रूप में काम करके, एफपीओ किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आदानों (जैसे-बीज, खाद आदि) खरीदने, प्राथमिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और सामूहिक मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर रिटर्न पाने में सक्षम बनाते हैं। इसी तरह, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और एग्री-क्लिनिक और एग्रीबिजनेस सेंटर (एसीबीसी) सफल सेवा आधारित उद्यमों के रूप में उभरे हैं। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवलर, ड्रोन और आधुनिक कृषि उपकरणों की किराये की सेवाओं ने छोटे किसानों के लिए भी उन्नत मशीनीकरण को सुलभ बना दिया है, साथ ही कृषि स्नातकों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए लाभदायक उद्यम भी तैयार किए हैं।

अपर्याप्त सुविधाएं, कमजोर मूल्य शृंखला और सीमित प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इन्हें फसल कटाई के तुरंत बाद मजबूरी में अपनी उपज बेचनी पड़ती है। अनुमान है कि कटाई के बाद होने वाली बर्बादी, खासकर फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के मामले में, भारत को प्रत्येक



उन्नत सिंचाई तकनीक से टिकाऊ कृषि

वर्ष भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे मूल्य संवर्धन और कुशल सप्लाय चैन मैनेजमेंट की तत्काल जरूरत का पता चलता है। जलवायु परिवर्तन ने कृषि उत्पादन से जुड़े जोखिमों को और बढ़ा दिया है। सूखे, बाढ़, लू, अनियमित बारिश, बेमौसम बारिश और कीटों व रोगों के प्रकोप की बढ़ती घटनाओं ने कृषि को अर्थव्यवस्था के सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बना दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 में जलवायु में बदलाव को कृषि उत्पादकता और आय की स्थिरता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में पहचाना गया है, खासकर उन छोटे किसानों के लिए जिनकी अनुकूलन क्षमता

सीमित है। जैसे-जैसे जलवायु से जुड़े जोखिम बढ़ रहे हैं, किसी एक फसल या खेती से होने वाली आय के किसी एक स्रोत पर निर्भर रहना अब टिकाऊ नहीं रह गया है।

भारतीय कृषि में साथ-साथ जनसांख्यिकीय बदलाव भी हो रहा है। खेती से कम मुनाफा, रोजगार के सीमित अवसर और खेती को कम लाभकारी व्यवसाय मानने की धारणा के कारण ग्रामीण युवा तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। 'पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे' से पता चलता है कि युवा कामगार धीरे-धीरे खेती से दूर हो रहे हैं, कृषि कार्यबल के वृद्ध होने और भविष्य में खेती के टिकाऊपन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। साथ ही, खेती के काम में लगी कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी है, फिर भी कई महिलाओं को जमीन के मालिकाना हक, संस्थागत लोन, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, कौशल विकास और बाजार में भागीदारी से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये असमानताएं इस सेक्टर की उत्पादकता क्षमता को और भी सीमित करती हैं।

ग्रामीण आजीविका में विविधता की आवश्यकता

पिछले दो दशकों में ग्रामीण भारत की आजीविका के स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव आया है। खेती का मतलब अब सिर्फ

सारणी 1. किसान से कृषि उद्यमी तक

पारंपरिक किसान	कृषि उद्यमी
मुख्य रूप से उत्पादन पर केंद्रित।	उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को एकीकृत करता है।
कच्चे कृषि उत्पादों की बिक्री करता है।	मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं विकसित करता है।
मौजूदा बाजार मूल्यों के अनुसार काम करता है।	विशिष्ट बाजारों की पहचान करता है और मांग उत्पन्न करता है।
मूल्य स्वीकारकर्ता के रूप में कार्य करता है।	ब्रांड बनाता है और उच्च बाजार मूल्य के लिए मूल्य पर बेहतर सौदेबाजी करता है।
मौसमी आय अर्जित करता है।	पूरे वर्ष कई आय स्रोत उत्पन्न करता है।
मुख्य रूप से पारंपरिक पद्धतियों पर निर्भर रहता है।	नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रबंधन को अपनाता है।
खेती को एक व्यवसाय के रूप में देखता है।	कृषि को एक सतत उद्यम के रूप में प्रबंधित करता है।

फसल उगाना नहीं रह गया है; बल्कि यह एक विविध आर्थिक व्यवस्था बन गई है, जिसमें पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इनपुट सप्लाई, कृषि-सेवाएं और डिजिटल कॉमर्स शामिल हैं। यह बदलाव लोगों की बदलती खपत की आदतों, बाजार के एकीकरण, तकनीकी प्रगति और परिवार की स्थिर आय की बढ़ती जरूरत के कारण आया है। ‘खेती करने वाले परिवारों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण’ (एनएसएस 77वां राउंड, 2019) के आंकड़े इस बदलाव को साफ तौर पर दिखाते हैं। खेती करने वाले परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये आंकी गई थी, जिसमें से सिर्फ 37.7 प्रतिशत आय फसल उगाने से आती थी। इसके विपरीत, 39.8 प्रतिशत आय मजदूरी से, 15.5 प्रतिशत पशुपालन से और बाकी 6.7 प्रतिशत खेती से अलग व्यावसायिक गतिविधियों से आती थी। ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण परिवारों का आर्थिक आधार अब खेती से होने वाली एकल आय से हटकर आजीविका के विविध स्रोतों की ओर बढ़ गया है। फसल उगाना अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह परिवार की समृद्धि का एकमात्र आधार नहीं रह गया है।

आजीविका बढ़ाने में सहायक कृषि क्षेत्र (एलाइड सेक्टर्स) प्रमुख प्रेरक शक्ति बनकर उभरे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है और वैश्विक दूध उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है। वहीं, वर्ष 2023-24 में मछली पालन क्षेत्र में सालाना उत्पादन 18 मिलियन टन से ज्यादा रहा। बागवानी क्षेत्र ने मूल्य प्राप्ति के मामले में लगातार अनाज उत्पादन से बेहतर प्रदर्शन किया है और यहां सालाना 360 मिलियन टन से ज्यादा फल और सब्जियां का उत्पादन होता है।

ये क्षेत्र प्रति इकाई क्षेत्र में ज्यादा



उच्च मूल्य बागवानी से आय के नए अवसर

रिटर्न देते हैं, नियमित नकद आय सुनिश्चित करते हैं और वर्षभर रोजगार उत्पन्न करते हैं, जिससे ये सीमित जमीन वाले छोटे किसानों के लिए खासतौर पर आकर्षक बन जाते हैं।

एक और अहम बदलाव एग्रीकल्चरल मूल्य श्रृंखला (खेती से जुड़ी पूरी प्रक्रिया) का बढ़ता महत्व है। पहले किसान सिर्फ फसल उगाकर ही कमाई करते थे। आज, फसल कटने के बाद सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्ट और रिटेलिंग के जरिए काफी वैल्यू जोड़ी जाती है।

विडंबना यह है कि किसानों को अक्सर अंतिम उपभोक्ता कीमत का बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है, क्योंकि ज्यादातर मूल्य संवर्धन खेत से बाहर होता है। इन

फसलोपरांत गतिविधियों में ग्रामीण लोगों की भागीदारी बढ़ाकर, बिना ज्यादा जमीन या ज्यादा उत्पादन के भी आय को काफी बढ़ाया जा सकता है। खाने-पीने की आदतों में तेजी से हो रहे बदलाव रोजगार के नए मौके उत्पन्न कर रहे हैं।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होने और खान-पान की बदलती पसंद के कारण प्रसंस्कृत खाद्य, डेरी उत्पादों, ऑर्गेनिक उत्पादों, रेडी-टू-कुक फूड, न्यूट्रास्युटिकल्स, श्री अन्न (मिलेट) से बने उत्पादों और ऐसे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है, जिनके स्रोत का पता लगाया जा सके।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय के अनुसार, भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मैनुफैक्चरिंग ग्रांस् वैल्यू एडेड का लगभग 13 प्रतिशत है और यह अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र में से एक है। यह



तकनीकी ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता से उन्नति

सारणी 2. भारत में कृषि-आधारित आजीविका संवर्धन हेतु उभरते कृषि उद्यमिता अवसर

एग्रीप्रेन्योरशिप का मौका	शुरुआती निवेश	कमाई की संभावना	मुख्य लाभार्थी
फूड प्रोसेसिंग	मध्यम	बहुत ज्यादा	महिला एसएचजी, एफपीओ
ड्रोन-आधारित कृषि सेवाएं	ज्यादा	ज्यादा	ग्रामीण युवा, कृषि स्टार्टअप
मशरूम की खेती	कम	ज्यादा	छोटे किसान, महिलाएं
संरक्षित खेती	मध्यम	ज्यादा	प्रगतिशील किसान
बीज उत्पादन	मध्यम	ज्यादा	एफपीओ, बीज उत्पादक
जैविक खेती	मध्यम	बेहतर रिटर्न	निर्यात-उन्मुख किसान
वेस्ट-टू-वेल्थ (कचरे से कमाई) उद्यम	कम	मध्यम	एकीकृत कृषि प्रणालियां



कौशल विकास से आत्मनिर्भरता की ओर



प्रसंस्करण आधारित उद्यमिता से मूल्य संवर्धन

बढ़ता हुआ बाजार प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग से जुड़े ग्रामीण उद्यमों के लिए बहुत सारे मौके देता है।

साथ ही, खेती के क्षेत्र में एक नई सेवा आधारित अर्थव्यवस्था भी उभर रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन से छिड़काव, मृदा की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं, प्रिंसिजन फार्मिंग परामर्श सेवाएं, डिजिटल सलाह सेवाएं, इनपुट रिटेलिंग, पौधे तैयार करना, खेती के मशीनीकरण की सेवाएं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे उद्यम बिना बड़ी जमीन के भी रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं।

ज्ञान पर आधारित ये उद्यम पढ़े-लिखे ग्रामीण युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और साथ ही महिलाओं, उत्पादक संगठनों और स्टार्टअप्स के लिए भी मौके बना रहे हैं। इसलिए, ग्रामीण आजीविका अब सिर्फ फसल की मात्रा से नहीं, बल्कि पूरी एग्रीकल्चरल मूल्य श्रृंखला में शामिल होने की क्षमता से तय होती है।

उत्पादन तो आधार बना हुआ है, लेकिन टिकाऊ आय अब ज्यादातर मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग, सेवाओं, टेक्नोलॉजी और बाजार से जुड़ाव पर निर्भर करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहा यह बदलाव एग्रीप्रेन्योरशिप (कृषि-उद्यमिता) के उभरने के लिए एक आदर्श माहौल बनाता है, जहां खेती को सिर्फ खेती-बाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे गतिशील उद्यम के तौर पर देखा जाता है, जो रोजगार, नवाचार और लंबे समय तक आजीविका की सुरक्षा देने में सक्षम है।

कृषि-उद्यमिता के नए मौके: ग्रामीण उद्यमों की अगली पीढ़ी को बढ़ावा

भारतीय कृषि का उत्पादन-केंद्रित व्यवस्था से बाजार उन्मुख उद्यम में बदलना कृषि उद्यमिता के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहा है। 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाला भारत का खाद्य और कृषि

क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

साथ ही, तेजी से शहरीकरण, खान-पान की बदलती पसंद, डिजिटलीकरण, संगठित खुदरा व्यापार और सुरक्षित, ट्रेस करने योग्य और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग कृषि बाजारों को नया रूप दे रही है। इन बदलावों ने खेती से कहीं आगे उद्यमिता के अवसर बढ़ा दिए हैं, जिससे किसान पूरी कृषि मूल्य श्रृंखला में भाग ले सकते हैं-आदान आपूर्ति और उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और खुदरा बिक्री तक।

मूल्यवर्धन: उपज को मुनाफे में बदलना

सबसे फायदेमंद अवसरों में से एक मूल्यवर्धन है, जहां कृषि उत्पादों को प्रीमियम उपभोक्ता उत्पादों में बदला जाता है।

सारणी 3. भारत में एग्रीप्रेन्योरशिप का सहायक संस्थागत इकोसिस्टम

सहायता के क्षेत्र	प्रमुख संस्थान/योजनाएं	दी जाने वाली मुख्य मदद
वित्तीय सहायता	पीएमपीएमई, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, पीएमईजीपी, एनएबीएआरडी	रियायती लोन, कैपिटल सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वर्किंग कैपिटल, एंटरप्राइज फाइनेंसिंग
स्टार्टअप और नवाचार सपोर्ट	स्टार्टअप इंडिया, अटल नवाचार मिशन, एग्री उड़ान, आरकेवीवाई-रफ्तार, एमएएनएजीई इनक्यूबेशन सेंटर	इनक्यूबेशन, सीड फंडिंग, मेंटरिंग, टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन, इन्वेस्टर से जुड़ाव
सामूहिक उद्यमिता	किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एसएफएसी, एनएबीएआरडी, एनसीडीसी	एकत्रीकरण, सामूहिक मार्केटिंग, इनपुट की खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, बाजार से जुड़ाव
कौशल विकास और क्षमता निर्माण	आईसीएआर संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एमएएनएजीई, आरएसईटीआई	उद्यमिता प्रशिक्षण, बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, कौशल विकास
महिला उद्यमिता	डीएवाई-एनआरएलएम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), लखपति दीदी पहल, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (नीति आयोग)	उद्यमों को प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशन, मेंटरिंग, डिजिटल सशक्तिकरण, बाजार तक पहुंच
बाजार और डिजिटल जुड़ाव	ई-एनएएम, ओएनडीसी, जीइएम, एपीईडीए, कृषि निर्यात नीति	डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट इंटेलिजेंस, निर्यात, ऑनलाइन ट्रेडिंग, खरीदार-विक्रेता संपर्क



मधुमक्खी पालन बना उद्यमिता का मधुर आधार

मूल्यवर्धन न केवल भंडारण क्षमता बढ़ाता है और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है, बल्कि उपभोक्ता कीमत में किसानों की हिस्सेदारी में भी काफी सुधार करता है।

कई विकसित देशों की तुलना में भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्तमान में अपनी बागवानी उपज का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही संसाधित करता है, जो काफी अप्रयुक्त क्षमता का संकेत देता है। अचार, जैम, फलों के पेय, सूखी सब्जियां, बाजरा-आधारित नाश्ते के अनाज, बकरी उत्पाद और पकाने के लिए तैयार खाद्य उत्पाद बनाने वाले ग्रामीण उद्यमों की घरेलू और निर्यात मांग बढ़ रही है।

डेरी क्षेत्र मूल्य आधारित उद्यमिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत सालाना 250

मिलियन टन से अधिक दूध का उत्पादन करता है, जो वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग एक चौथाई है, जिसमें भैंसों का योगदान राष्ट्रीय दूध उत्पादन का लगभग आधा है। अधिक वसा और कुल ठोस सामग्री के कारण, भैंस का दूध मोजेरेला चीज, पनीर, खोया, खोया-आधारित मिठाइयां और घी जैसे प्रीमियम उत्पाद बनाने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और प्रत्यक्ष विपणन के साथ एकीकृत वैज्ञानिक भैंस पालन किसानों की आय में काफी वृद्धि कर सकता है और साथ ही ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न कर सकता है।

तकनीक संचालित कृषि-उद्यमिता

कृषि तेजी से एक तकनीक प्रधान क्षेत्र बनती जा रही है। आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सैटेलाइट इमेजिंग, रोबोटिक्स और प्रिसिजन एग्रीकल्चर (सटीक कृषि) के आगमन ने कृषि व्यवसाय की एक बिल्कुल नई श्रेणी बनाई है।

महंगी तकनीकों में व्यक्तिगत रूप से निवेश करने के बजाय, किसान तेजी से उन विशेष उद्यमियों पर निर्भर हो रहे हैं, जो किराए के आधार पर ड्रोन छिड़काव, मृदा के स्वास्थ्य की जांच, सटीक सिंचाई, डिजिटल फसल निगरानी और कृषि मशीनीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सेवाएं इकॉनमी न केवल उत्पादन की लागत को कम करती है, बल्कि तकनीकी रूप से कुशल ग्रामीण युवाओं के लिए उच्च-मूल्य वाले रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करते हैं।

उच्च-मूल्य और जलवायु-अनुकूल उद्यम

खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता ने जैविक और प्राकृतिक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पादों की मांग को बढ़ा दिया है। भारत में जैविक प्रमाणन के तहत दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिससे मसालों, औषधीय पौधों, कॉफी, चाय और बागवानी फसलों के निर्यात के महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हुए हैं।

साथ ही, पॉलीहाउस, शेड-नेट हाउस और हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से संरक्षित खेती सब्जियों, फूलों और विदेशी फसलों के वर्षभर उत्पादन को सक्षम बनाती है, जिसमें उत्पादकता अधिक होती है और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग होता है। कई संबद्ध उद्यम भी अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ आकर्षक आर्थिक रिटर्न देते हैं। मशरूम की खेती, बीज उत्पादन, बकरी

कृषि नवाचार एवं उद्यमिता

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी कृषि नवाचार को बढ़ावा देने वाले एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय पहलें जैसे स्टार्टअप इंडिया, अटल नवाचार मिशन, आरकेवीवाई-रफ्तार एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम, एग्री उडान और भाकूअनुप संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर मेंटरशिप, बिजनेस इनक्यूबेशन, सीड फंडिंग, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन और इन्वेस्टर नेटवर्किंग की सुविधा देते हैं। इन प्रोग्राम्स ने कई स्टार्टअप्स को सटीक खेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, फार्म मशीनीकरण, बायोटेक्नोलॉजी, सप्लाय-चेन मैनेजमेंट और डिजिटल कृषि में इनोवेटिव समाधान विकसित करने में सक्षम बनाया है। किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने से सामूहिक उद्यमिता को काफी गति मिली है। स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राज्य सरकारों जैसी एजेंसियों के सपोर्ट से, एफपीओ किसानों की सौदेबाजी क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। वे इनपुट की सामूहिक खरीद, उपज का एकीकरण, प्राइमरी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सीधे मार्केटिंग की सुविधा देकर ऐसा करते हैं। छोटे किसानों को शेयर होल्डर-उद्यमी बनाकर, एफपीओ बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। एग्रीप्रेन्योरशिप (कृषि-उद्यमिता) इकोसिस्टम का एक और अहम हिस्सा 'ड्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट' (मानव संसाधन विकास) है।

पालन, घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती और नर्सरी प्रबंधन से तेजी से आय होती है, उत्पादन का जोखिम कम होता है और रोजगार की अच्छी संभावनाएं होती हैं, खासकर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए।

डिजिटल एग्रीकल्चर और सर्कुलर बायो-इकोनॉमी

डिजिटल प्रौद्योगिकियां, खेती-बाड़ी से जुड़े कारोबारों के बाजार के साथ जुड़ने के तरीके को बदल रही हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्लाउडसेप बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल आधारित सलाह देने वाले सिस्टम और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर्मर्स की वजह से किसान सीधे ग्राहकों से जुड़ पा रहे हैं, बेहतर दाम पा रहे हैं और भौगोलिक सीमाओं से परे अपने बाजार का दायरा बढ़ा पा रहे हैं।

ये डिजिटल नवाचार धीरे-धीरे पारंपरिक मार्केटिंग चैनलों की जगह पारदर्शी, डेटा-आधारित बिजनेस मॉडल ले रहे हैं।

सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर आधारित 'वेस्ट-टू-वेल्थ' (कचरे से कमाई) वाले कारोबारों का उभरना भी उतना ही उम्मीद जगाने वाला है। खेती के अवशेषों और पशुओं के कचरे को तेजी से बायोगैस, बायो-फर्टिलाइजर, वर्मीकम्पोस्ट, बायोचार और जैविक खाद में बदला जा रहा है, जिससे अतिरिक्त कमाई के जरिया बन रहे हैं और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो रहा है। ऐसे कारोबार संसाधनों के इस्तेमाल की क्षमता को बेहतर बनाते हैं, उत्पादन लागत कम करते हैं और क्लाइमेट-स्मार्ट खेती में योगदान देते हैं।

इन मौकों की विविधता यह दिखाती है कि भारतीय खेती का भविष्य सिर्फ फसल उत्पादन से कहीं आगे तक फैला है। आज एग्रीप्रेन्योरशिप (खेती-बाड़ी से जुड़ी उद्यमिता) में मैनुफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्विस, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग, डिजिटल कॉमर्स और पर्यावरण की देखभाल शामिल है।

नवाचार को मार्केट इंटेलिजेंस और मूल्य संवर्धन के साथ जोड़कर, एग्रीप्रेन्योरशिप मजबूत ग्रामीण आजीविका बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और भारतीय खेती को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बिजनेस सेक्टर के तौर पर स्थापित करने का एक क्रांतिकारी रास्ता दिखाती है।



**संबल यानी सहयोग
सहयोग से बड़ेगा उद्योग**

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत:

- ♦ व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का उन्नयन
- ♦ एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं कॉपरेटिव को सहायता
- ♦ स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी
- ♦ सामान्य अवसंरचना के लिए अनुदान
- ♦ ब्रांडिंग और बिक्री सहायता
- ♦ एक जिला एक उत्पाद

सरकारी सहयोग से सशक्त बनते ग्रामीण खाद्य उद्यम

एग्रीप्रेन्योर्स (कृषि-उद्यमियों) की सहायता करने वाला संस्थागत इकोसिस्टम

भारत में एग्रीप्रेन्योरशिप (कृषि-उद्यमिता) की तेजी से बढ़ती ग्रोथ को एक मजबूत संस्थागत इकोसिस्टम से मदद मिली है। यह इकोसिस्टम उद्यमियों को उनके उद्यम के पूरे सफर में सहायता करता है—जैसे कि आइडिया सोचना और स्किल डेवलपमेंट से लेकर फाइनेंसिंग, इनक्यूबेशन, मार्केट तक पहुंच और उद्यम का विस्तार करना। यह समझते हुए कि उद्यमिता के लिए सिर्फ आर्थिक मदद से कहीं ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, भारत सरकार ने एक व्यापक तरीका अपनाया है।

इसमें पॉलिसी सपोर्ट, संस्थागत क्रेडिट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन और सामूहिक उद्यम विकास को शामिल किया गया है। इस बहुआयामी इकोसिस्टम ने कृषि उद्यमों को शुरू करने और उन्हें बढ़ाने (स्केल करने) को काफी आसान बना दिया है, खासकर ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, स्टार्टअप्स और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए। उद्यम विकास के लिए सस्ती फाइनेंसिंग तक पहुंच सबसे अहम है।

कई प्रमुख प्रोग्राम—जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और नाबार्ड के रीफाइनंस और क्रेडिट सपोर्ट प्रोग्राम—रियायती क्रेडिट, कैपिटल सब्सिडी और इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग

देते हैं। ये मदद मूल्यवर्धन, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कोल्ड चेन, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट और कृषि-आधारित सूक्ष्म उद्यमों के लिए दी जाती है। इन पहलों ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए आर्थिक बाधाओं को काफी कम किया है और साथ ही कृषि मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा दिया है।

कृषि विज्ञान केंद्र, भाकृअनुप संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नियमित रूप से उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कौशल बढ़ाने की पहल, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन और बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आयोजित करते हैं। ये संस्थान उद्यमियों को टेक्निकल, मैनेजमेंट और मार्केटिंग से जुड़ी काबिलियत देकर वैज्ञानिक नवाचार और उनके कमर्शियल इस्तेमाल के बीच की दूरी को कम करते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले एग्री-बिजनेस को बढ़ावा देने पर भी खास जोर दिया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी पहल और नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म जैसी पहलों ने महिलाओं की फाइनेंस, उद्यम विकास, डिजिटल साक्षरता, मेंटरिंग और मार्केट लिंकेज तक पहुंच बढ़ाई है।

इन परस्पर जुड़े संस्थानों ने एग्रीप्रेन्योरशिप को एक अकेले व्यक्ति के प्रयास से बदलकर एक सुदृढ़ सहयोगात्मक पारितंत्र में परिवर्तित कर दिया है—फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इनक्यूबेशन,

क्षमता निर्माण और मार्केट इंटीग्रेशन के मेल से एक ऐसा माहौल बन रहा है, जहां नए और अनोखे कृषि उद्यम फल-फूल सकते हैं।

इससे आजीविका में विविधता, रोजगार के अवसर और ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ बदलाव को तेजी मिलती है।

चुनौतियां

भारत में एग्रीप्रेन्योरशिप तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई जुड़ी हुई रुकावटें इसके बड़े पैमाने पर अपनाए जाने में बाधा डाल रही हैं, खासकर छोटे किसानों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के बीच। ये चुनौतियां सिर्फ कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मुख्य रूप से उद्यमिता से जुड़ी क्षमताओं, संस्थागत सहायता प्रणालियों और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता से संबंधित हैं। ग्रामीण आजीविका में बदलाव लाने वाले एक जरिया के तौर पर एग्रीप्रेन्योरशिप की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए निम्न रुकावटों को दूर करना जरूरी है:

व्यक्तिगत और उद्यमिता से जुड़ी बाधाएं
एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए उत्पादन-केंद्रित



कृषि पर्यटन (एग्री टूरिज्म) से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा

सोच से हटकर उद्यम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है। हालांकि, कई इच्छुक उद्यमी जोखिम लेने से बचने, उद्यमिता के प्रति सीमित रुचि और व्यवसाय प्रबंधन संबंधी सीमित कौशल के कारण कृषि-उद्यम शुरू करने में हिचकिचाते हैं। बिजनेस प्लान तैयार करना, बाजार की मांग का आकलन करना, वित्तीय रिकॉर्ड रखना, गुणवत्ता मानकों

का पालन करना और उद्यमों का प्रबंधन करने के लिए ऐसी क्षमताओं की जरूरत होती है, जो अक्सर पहली पीढ़ी के उद्यमियों में नहीं होती है। सफल बिजनेस मॉडल की कम जानकारी भी नवाचार और उद्यम के विस्तार को सीमित करती है।

वित्तीय बाधाएं

हालांकि कई संस्थागत क्रेडिट प्रोग्राम मौजूद हैं, लेकिन समय पर और किफायती फाइनेंस (पूंजी) तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई ग्रामीण उद्यमियों, खासकर युवाओं और महिलाओं के पास वित्तीय संस्थानों द्वारा जरूरी कोलेटरल सिक्क्योरिटी (गिरवी रखने के लिए संपत्ति), औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री या जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं होते हैं। नतीजतन, वे अक्सर अनौपचारिक उधार पर निर्भर रहते हैं, जिससे पूंजी की लागत बढ़ जाती है और उद्यम का विकास सीमित हो जाता है। शुरुआती दौर के एग्रीबिजनेस को भी कामकाज के शुरुआती वर्षों में वर्किंग कैपिटल जुटाने और निवेश आकर्षित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

संस्थागत और क्षमता से जुड़ी बाधाएं

एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए सहायता कई मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है; हालांकि, संस्थागत तालमेल और अंतिम स्तर तक समन्वय सीमित रहता है। उद्यमियों को अक्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनक्यूबेशन सुविधाओं, सब्सिडी, बाजार सहायता और क्रेडिट योजनाओं के बारे में बिखरी हुई जानकारी मिलती है। अनुसंधान संस्थानों, विस्तार एजेंसियों, वित्तीय संगठनों और निजी उद्यमों के बीच कमजोर जुड़ाव के कारण इनोवेटिव तकनीकों और बिजनेस आइडिया के

भावी परिदृश्य

एग्रीप्रेन्योरशिप (कृषि-उद्यमिता) में भारतीय कृषि के भविष्य को बदलने की क्षमता है। यह किसानों को केवल प्राथमिक उत्पादक के रूप में ही नहीं, बल्कि मूल्य संवर्धन करने वाले उद्यमी तथा ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले उद्यमी के रूप में भी विकसित कर सकती है। हालांकि, इस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे तालमेल वाले इकोसिस्टम की जरूरत है, जो शिक्षा, नवाचार, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, बाजार और पॉलिसी सपोर्ट को एक साथ लाए। भारतीय कृषि का भविष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि एक ऐसी उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने पर निर्भर करेगा, जो ग्राहकों की तेजी से बदलती मांगों और ग्लोबल मार्केट के मौकों के हिसाब से ढल सके। उद्यमिता की शिक्षा कृषि पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत स्कूल स्तर से हो और जो यूनिवर्सिटी और वोकेशनल संस्थानों तक पहुंचे। तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ, युवा सीखने वालों को एंटरप्राइज प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरसी, डिजिटल मार्केटिंग और नवाचार के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। कृषि स्नातकों को नौकरी खोजने के बजाय रोजगार सृजित करने वाला उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप एक्सेलेरेटर और मेंटरशिप प्रोग्राम का सहारा लिया जा सकता है, जो नए और अनोखे विचारों को कमर्शियल रूप से सफल बिजनेस में बदल सकें। कृषि में बदलाव के अगले चरण को डिजिटल और क्लाइमेट-स्मार्ट उद्यमिता के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, सैटेलाइट-आधारित सलाह सेवाएं और प्रिसिजन एग्रीकल्चर तेजी से ग्लोबल फूड सिस्टम को बदल रहे हैं। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और इन टेक्नोलॉजी तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने से ग्रामीण उद्यमी उत्पादकता बढ़ा पाएंगे, संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की क्षमता मजबूत कर पाएंगे। साथ ही, क्लाइमेट-स्मार्ट उद्यमों जैसे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन-स्मार्ट खेती, बायो-इनपुट प्रोडक्शन और सर्कुलर बायो-इकोनॉमी पहलों में ज्यादा निवेश से पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करते हुए टिकाऊ बिजनेस के मौके उत्पन्न होंगे।

कमर्शियलाइजेशन (व्यावसायीकरण) में और देरी होती है।

बाजार और मूल्य शृंखला की बाधाएं

कृषि व्यवसाय की सफलता न केवल उत्पादन पर बल्कि बाजार तक पहुंच और उत्पाद विविधीकरण पर भी निर्भर करती है। कई ग्रामीण उद्यम ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, मानकीकरण और रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करते रहते हैं, जिससे संगठित खुदरा और निर्यात बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित हो जाती है। अपर्याप्त भंडारण, शीत शृंखला अवसंरचना और परिवहन सुविधाएं विपणन लागत को बढ़ाती हैं और उत्पाद की गुणवत्ता को कम करती हैं, विशेष रूप से नाशवान वस्तुओं के लिए। इसके अलावा, सीमित बाजार जानकारी अक्सर उद्यमियों को लाभदायक बाजार क्षेत्रों की पहचान करने और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रतिक्रिया देने से रोकती है।

तकनीकी और डिजिटल चुनौतियां

डिजिटल कृषि का तीव्र विस्तार अनेक नए अवसर प्रदान करता है, फिर भी डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी को अपनाने का स्तर असमान बना हुआ है, विशेष रूप से छोटे किसानों के बीच। डिजिटल भुगतान प्रणालियों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों, कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सलाहकार सेवाओं और ऑनलाइन विपणन उपकरणों से सीमित परिचय उद्यमियों को उभरते व्यावसायिक अवसरों का पूरा लाभ उठाने में बाधा बनता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल विभाजन को और भी बढ़ा देती है।

नीतिगत और नियामक चुनौतियां

कृषि व्यवसाय उद्यमों की स्थापना के लिए अक्सर व्यवसाय पंजीकरण, खाद्य सुरक्षा मानकों, लाइसेंसिंग, कराधान, पर्यावरण नियमों और गुणवत्ता प्रमाणन से संबंधित कई नियामक प्रक्रियाओं का अनुपालन आवश्यक होता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए ये प्रक्रियाएं समय लेने वाली और तकनीकी रूप से जटिल हो सकती हैं।

नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, एकल-खिड़की सुविधा प्रणालियों को मजबूत करना और नीतिगत समन्वय में सुधार करना कृषि उद्यमशीलता के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये बाधाएं उद्यम विकास को प्रभावित करती



तकनीकी नवाचार से सशक्त होती कृषि उद्यमिता

रहती हैं, साथ ही ये नीतिगत हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी उजागर करती हैं। उद्यमशीलता क्षमता को मजबूत करना, संस्थागत समन्वय में सुधार करना, डिजिटल समावेशन का विस्तार करना, वित्त तक पहुंच को सफल बनाना और कुशल बाजार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना कृषि उद्यमशीलता के नेतृत्व में ग्रामीण परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत की एग्रीप्रेन्योरशिप (कृषि-उद्यमिता) रणनीति के केंद्र में महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को होना चाहिए। स्वयं-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, डेरी सहकारी समितियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का विस्तार करने से परिवारों की आय में काफी बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है।

इसी तरह, एग्रीगेशन (एकत्रीकरण), प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात के क्षेत्रों में एफपीओ के नेतृत्व वाले कृषि-व्यवसायों को मजबूत करने से छोटे किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी; इससे उन्हें बड़े पैमाने पर काम करने (इकानॉमी ऑफ स्केल) और बाजार में बेहतर मोल-भाव करने की ताकत मिलेगी।

भविष्य की नीतियों में ब्रांडिंग, गुणवत्ता की गारंटी, भौगोलिक संकेत (जीआई) वाले उत्पादों, निर्यात पर ध्यान

देने और डिजिटल कॉमर्स पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण उद्यम स्थानीय बाजारों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शृंखला में शामिल हो सकें।

सरकारी एजेंसियों, भाकृअनुप संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स, वित्तीय संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिए मजबूत सहयोग से टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन, निवेश और उद्यम विकास में तेजी आएगी।

‘उत्पादक से प्रोसेसर, प्रोसेसर से उद्यमी और उद्यमी से ग्लोबल एग्रीबिजनेस लीडर’ तक का सफर भारतीय कृषि के विकास का अगला चरण है। नवाचार को बढ़ावा देकर, संस्थानों को मजबूत करके और उद्यम विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाकर, एग्रीप्रेन्योरशिप टिकाऊ आजीविका, ग्रामीण रोजगार और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है।

‘विकसित भारत 2047’ के विजन में भारतीय कृषि की सफलता का आकलन केवल रिकॉर्ड उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि ऐसे सफल एग्रीप्रेन्योर्स की संख्या के आधार पर भी किया जाएगा, जो मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, रोजगार सृजित कर रहे हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।